केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग में **30%** वेतन वृद्धि की पुष्टि

"सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों का वेतन हर पाँच वर्षों में एक बार संशोधित होता है. हाल के 10वें द्विपक्षीय वेतन अनुबंध ने उन्हें 15% की वृद्धि प्रदान की."

संयुक्त बैंक संघ फोरम (UFBU) ने प्रारंभ में 21% वेतन वृद्धि की माँग रखी थी. यह वार्ताओं की एक वृहद श्रृंखला के बाद ही हुआ कि भारतीय बैंक संगठन 15% के लिए समायोजन हेतु सहमत हुए.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्रत्येक दस वर्षों में एक बार, वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है. आयोग केंद्रीय स्टाफ की वेतन संरचना, छूटों और सुविधाओं/लाभों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों का जाँच उन्हें दिए गए संदर्भ शर्तों के आधार पर करेगी. आयोग को इसके गठन की दिनांक के 18 माहों के अंदर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना पड़ती हैं.

सभी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों, संगठनों और संघों को समिति से मिलने और उनकी माँगों और अपेक्षाओं को ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है. ये सभी चरण पूर्ण कर लिए गए हैं. वेतन आयोग से अपनी रिपोर्ट को इसी माह केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है.

प्रमुख प्रश्न जो स्वभाविक रूप से हर व्यक्ति के दिमाग में आता है – केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितनी वृद्धि प्राप्त होगी**?**

हमारे दृष्टिकोण से, सभी केंद्रीय कर्मचारी, चाहे किसी भी श्रेणी और सेवाकाल के हों, वेतनों में निश्चित रूप से एकसमान 30% वृद्धि 01.01.2016 से प्राप्त करेंगे.

माना कि एक कर्मचारी, जिसको 6वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद भर्ती किया गया था, सभी भत्तों सहित औसतन रु. 30,000 प्राप्त करता है. फिर 7वें वेतन आयोग के क्रियान्यन के बाद, उसके वेतन में 30% की वृद्धि होगी और उसका वेतन रु. 39,000 होगा.

प्रत्येक व्यक्ति, एनसी जेसीएम और समाचार वेबसाइटों सहित, अधिकतम वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है. वह पूर्ण रूप से उनकी समझ है. उनके पास एक कारण भी होगा – आसान कारण है 'यदि आप वह प्राप्त करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो आपको उससे अधिक माँगना चाहिए'. वे 60% से 70% वृद्धि की आशा कर रहे हैं.

यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश गलत धारणाएँ उत्पन्न होती हैं. अंग्रेजी समाचारपत्र भी अपवाद नहीं हैं, और उन्होंने गलत आँकड़े दिए हैं.

"न्यूनतम मूलभूत वेतन, जैसा 6वें वेतन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था, रु. 7000 था. निम्नतम श्रेणी कर्मचारी, जिसे 6वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद भर्ती किया गया था, उसका मूलभूत वेतन रु. 7000 प्रतिमाह तथा भत्ते अलग से थे. लगभग दस वर्ष बाद, समान निम्नतम श्रेणी कर्मचारी, जिसे जुलाई 2015 के बाद भर्ती किया गया था, उसका मूलभूत वेतन रु. **15330 (7000 + 119%** डीए) और भत्ते है. महँगाई भत्ता, जो एक वर्ष में दो बार दिया जाता है, शून्य पर शुरु हुआ और पिछले 10 वर्षों में **119%** तक बढ़ा है**".**

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन, एनसी जेसीएम स्टाफ साइड, ने 7वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए अपने ज्ञापन में, रु. 15330 के बजाय रु. 26000 के संशोधित न्यूनतम मूलभूत वेतन की आशा की. संघ ने उनकी माँगों के लिए अखंडनीय व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के साथ वर्णन और बचाव किया था.

समाचार माध्यमों में, संघ वेतन में 3 गुना वृद्धि की माँग कर रहा है इस आधार पर प्रश्न करते हुए आलेख लिखे जा रहे हैं**..?**

वास्तव में, यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस आधार पर आलेखों को प्रकाशित कर रहे हैं कि संघ 3 गुना वेतन वृद्धि की माँग कर रहा था और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 3 गुना वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं**!**

'किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि वेतन आयोग, वेतन संशोधन, पदोन्नति, इत्यादि सहित अनेक घटकों पर निर्भर करती है. वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करने की सामान्य प्रक्रिया पूर्व-वृद्धि वेतन के आधार पर इसका परिकलन करना है. किंतु, यह देखना हास्यास्पद है कि कुछ लोग दस वर्ष पूर्व कर्मचारी द्वारा लिए गए वेतन के आधार पर वृद्धि का परिकलन करते हैं और दावा करते हैं कि वे कई गुना वेतन वृद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं.'

उन कर्मचारियों को, जिन्हें **2.86** के गुणन घटक के भ्रमित करने वाले दावे द्वारा ललचाया जाता है, उन्हें ऐसा मानते हुए देखना दुखदायक है कि तीन गुना वेतन वृद्धि होगी.

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन जनवरी 2016 से दिसंबर 2015 के वेतन की अपेक्षा 30% अधिक होंगे.

वे लोग जो इस मत से भेद रखते हैं, और जो आश्वस्त हैं कि यह बहुत कम है, उनसे दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 की वेतन वृद्धि के प्रतिशत का परिकलन करने का अनुरोध किया जाता है. यह 6वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वृद्धि थी. इसके अतिरिक्त, यदि संभव हो, तो दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के वेतन में वृद्धि ज्ञात करने का प्रयास कीजिए. यह 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वृद्धि थी.

यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार का जादू छा जाता है जब वेतन वृद्धि की बात आती है. यह भ्रम को तोड़ने का एक प्रयास है.

मैं इस आलेख को आपकी सम्माननीय प्रतिक्रिया के साथ प्रारंभ करूँगा.

Author: Ushanandhini TE

Blog: www.90paisa.blogspot.com

Date : 2.8.2015